अमित शाहः भारत का नया जनरल डायर

-वाई. के. रज्जन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नं. 2 अमित शाह की राजनीति का अंत होने वाला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को अभी हाल तक देश का नं. 2 और पार्टी का महारणनीतिकार बताकर महिमामंडित किया जा रहा था लेकिन सूरत और जींद ने इस शख्स का हुलिया बिगाड़ दिया है। देश-विदेश के अखबारों, मैगजीनों और टीवी चैनलों में इस शख्स को सबसे ताकतवर नेता बताया जा रहा था।

केंद्रीय मंत्री चौधरी बिरेंद्र सिंह उन्हें 11 सितंबर को जींद में गौरव रैली में लेकर आए थे। ये गौरव रैली किस चीज की थी ये तो पता नहीं लेकिन इसकी आड़ में बिरेंद्र अपना कद बढ़ाना चाहते थे। उनका एक बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए वो प्रयासरत हैं और वहां तक उनको सिर्फ अमित शाह ही पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मोदी वही करते हैं जो अमित शाह चाहते हैं। गौरव रैली में सब कुछ ठीक चल रहा था। स्टेज पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय नितिन गडकरी और खट्टर के कई मंत्री बैठे थे। इतने में स्टेज के ठीक सामने कुछ लोग काले झंडे लेकर उठे और उन्होंने भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरु कर दिए। मोदी, अमित शाह और खट्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। शाह से लेकर सारे मंत्री और सीएम की हालत बिगड़ गई। अमित शाह का चेहरा लाल...क्योंकि इससे पहले जब तमाम मंत्री, सीएम और बिरेंद्र सिंह बोल रहे थे तो कोई हरकत नहीं हुई थी लेकिन जैसे ही अमित शाह बोलने खड़े हुए तो उन्हें काले झंडे दिखाने के साथ नारेबाजी शुरू हो गई। अमित शाह की जबान लड़खड़ा गई और उन्हें अपना भाषण जल्दबाजी में खत्म करना पड़ा। काला झंडा दिखाने वाले दरअसल जेबीटी शिक्षक थे और बेरोजगारी से तंग आकर यह काम कर बैठे थे। काले झंडे दिखाने का नतीजा यह निकला कि बिरेंद्र जो महत्वपूर्ण घोषणाएं करवाना चाहते थे, शाह ने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि घुमा फिराकर नसीहत दे डाली। बिरेंद्र ने अपने भाषण में कहा था कि सेंट्रल हरियाणा के साथ हमेशा अन्याय हुआ है।...इसका जितना विकास होना चाहिए था, वो कभी नहीं हुआ। पिछले सारे सीएम मतलबी निकले। बिरेंद्र ने जाटों को आरक्षण दिए जाने की भी मांग रखी और भाजपा के सांसद राजकुमार सैनी का नाम लिए बिना कहा कि हमारी ही पार्टी के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बदले में अमित शाह ने बिरेंद्र को नसीहत दी कि बिरेंद्र सिर्फ सेंट्रल हरियाणा के नेता नहीं हैं, उन्हें पूरे हरियाणा के बारे में सोचना चाहिए। हमारी पार्टी किसी क्षेत्र विशेष, जाति या बिरादरी की राजनीति में विश्वास नहीं रखती। यह हर वर्ग को लेकर चलती है। खैर इन बातों को मतलब आप निकालते रहें। अब सूरत की तरफ बढ़ते हैं।

जनरल डायर के पोस्टर

जींद रैली से पहले अमित शाह की एक रैली सूरत में 8 सितंबर को हुई थी। इस रैली ने गुजरात में भाजपा के सारी साख की हवा निकाल दी। सूरत के लोग जब 8 सितंबर को सोकर उठे तो उन्हें पूरा शहर जनरल डायर वापस जाओ के पोस्टरों से पटा पड़ा नजर आया। अमित शाह का फोटो लगा था और उनसे कहा जा रहा था कि वे वापस दिल्ली लौट जाएं। ये पोस्टर पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की ओर से लगाए गए थे। अगस्त 2015 में हार्दिक पटेल की पाटीदार रैली में जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ था, उसे पटेल भूले नहीं हैं। हालांकि तब आनंदी बेन पटेल गुजरात की सीएम थीं लेकिन उन्होंने इसके लिए हमेशा अमित शाह को ही जिम्मेवार माना। क्योंकि आनंदीबेन के भी समय अमित शाह ही गुजरात को लेकर सारे फैसले लेते थे और बाद में जब आनंदीबेन को हटाकर रुपाणी को नया सीएम बनाया गया तो भी वो फैसला शाह का था।

सूरत समारोह के आयोजनकर्ता बड़े-बड़े हीरा व्यापारी और टेक्सटाइल्स कंपनियों के कारोबारी थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि पटीदार विरोध कर सकते हैं। इसलिए अमित शाह के लिए जो स्टेज बनाया गया था उसे तीन तरफ से कंटीले तारों और लोहे की सलाखों से सुरक्षित कर दिया गया था ताकि कोई प्रदर्शनकारी स्टेज पर अमित शाह तक जाकर उन्हें कालिख न पोत सके। लेकिन विरोध करने वाले अपना रास्ता तलाश ही लेते हैं। प्रदर्शनकारी आम लोगों में शामिल होकर उन कुर्सियों पर जाकर बैठ गए, जिन्हें जनता के लिए लगाया था। अमित शाह ने भाषण शुरू ही किया था कि प्रदर्शनकारी उठ खड़े हुए और उन्होंने मोदी व अमित शाह पर सीधे अटैक करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। जनरल डायर गो बैक....मोदी-शाह मुर्दाबाद जैसे नारे वहां गूंज उठे और प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद उन कुर्सियों को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। वहां भगदड़ मच गई। शाह ने चंद मिनटों में अपना भाषण खत्म किया और फौरन स्टेज छोड़कर चले गए। अगले दिन नाराज मोदी ने आनंदीबेन को दिल्ली तलब किया। क्योंकि मोदी को बताया गया था कि आनंदीबेन का भी समर्थन प्रदर्शनकारियों को प्राप्त था। इन दोनों घटनाओं ने अमित शाह को उनकी औकात बता दी। लेकिन जुलाई में शाह की आगरा रैली को इसलिए रद्द करना पड़ा था कि उसमें दलित ही नहीं पहुंचे थे। इससे पहले गोवा में जब अमित शाह को काले झंडे दिखाए गए थे तो उन्होंने वहां के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष वेलिंगर को ही हटा दिया था। इसके बाद वेलिंगर ने अमित शाह की पोलपट्टी खोली कि ये शख्स कभी भी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करता, जो इसके पैर न छूते हों या इसे मोदी से भी ऊपर अपना नेता न मानते हों।

अमित शाह का अतीत

दरअसल, अमति शाह का अतीत उनका पीछा करता रहता है। 2002 के गुजरात दंगों के समय यह तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे विश्वासपात्र मंत्री था और इंडियन एक्सप्रेस ने एक टेलीफोन पर रिकॉर्ड की गई बातचीत को सार्वजनिक करते हुए बताया था कि कैसे इस मंत्री की दंगों में भूमिका रही है। इसी तरह गुजरात में जितने भी विवादास्पद एनकाउंटर हुए, उसमें इसकी भूमिका को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि कुछ अदालतों से इसे क्लीन चिट मिल गई लेकिन लोगों का मुंह कोई कैसे बंद कर सकता है। गुजरात में अगर आप जाएंगे तो पाएंगे कि इस इंसान से वहां के पटेल लोग कितनी घृणा कर रहे हैं।

बिहार और दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसे ही जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसने दोनों जगहों पर मोदी को ही बतौर चुनाव जिताने वाले नेता के रूप में पेश किया। पूंजीवादी मीडिया इसे महान रणनीतिकार बताकर बिहार और दिल्ली फतेह करने की जानकारी दे रहा था। लेकिन खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट थी कि दोनों राज्य सिर्फ और सिर्फ मोदी- शाह की कारस्तानी के कारण भाजपा हारने जा रही है। तब इसने अंतिम समय में इसने बड़ा दांव खेला। बिहार में अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन छपवाए गए। जिसमें गऊ माता को पेशकर उसे लालू-नीतिश के पंजे से बचाने की कोशिश की गई। इलेक्शन को सांप्रदायिक बनाने की यह ऐसी घिनौनी कोशिश थी कि न चाहते हुए भी चुनाव आयोग को भाजपा को नोटिस देना पड़ा। हालांकि हुआ कुछ नहीं। लेकिन वो विज्ञापन सीधे-सीधे हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए दिया गया था। इसी तरह इसने दिल्ली में अंतिम समय में पूर्व आईपीएस किरन बेदी को बतौर सीएम पेश करते हुए मैदान में उतार दिया जिससे हार का ठीकरा मोदी और शाह पर न फूटे। इसी चुनाव में उसने कहा था कि मोदी ने 15 लाख बैंकों में डालने की बात एक जुमले के तौर पर कही थी।...

दलाल मीडिया

मोदी राज में मीडिया की भूमिका बहुत ही गंदी और घटिया होती जा रही है। जींद और सूरत की घटना को टीवी चैनलों पर दिखाया ही नहीं गया। ऐसा लगा कि जैसे उन दोनों शहरों में कुछ हुआ ही नहीं है। चलिए जींद की घटना को बहुत छोटा मान लेते हैं लेकिन सूरत में जो कुछ हुआ, उसे तमाम तथाकथित अंग्रेजी-हिंदी राष्ट्रीय अखबारों ने पहले पेज पर जगह ही नहीं दी। न्यूज चैनलों सूरत की घटना को पी गए। किसी अखबार में इस पर संपादकीय नहीं लिखा गया। अखबारों में अब संपादकों को साफ-साफ निर्देश है कि वे मोदी और अमित शाह के खिलाफ कुछ नहीं छापेंगे। मुकेश अंबानी के 25 चैनल दिन-रात मोदी गुणगान में लगे रहते हैं। इनमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल हैं, जिन्हें अब मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया है और पूरा ग्रुप टीवी 18 के नाम से जाना जाता है।

संघ-भाजपा का संगठन मंथनः पानी बिलोने से मक्खन नहीं निकलता

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते पखवाड़े सूरजकुंड स्थित पचसितारा होटल राजहंस में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व भाजपा के दिग्गजों ने अपने सांगठनिक तालमेल को लेकर 4 दिनों तक गहन मंथन किया। इसमें संघ प्रचारक से मुख्यमंत्री बने खट्टर से लेकर तमाम प्रदेश स्तरीय भाजपा व संघ के नेता तो शामिल हुए ही थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता अमितशाह व भैया जी जोशी आदि भी शामिल हुए। पंचसितारा पर्यटन स्थल पर हुए इस पंचसितारा मंथन को बहुत ही गुप्त तरीके से कमरों में किया गया केवल छान-छान कर ही कुछ बातें मीडिया को परोसी गयीं।

संघ भाजपा चाहे कितना ही गुप्त मंथन कर लें, लेकिन सभी जानते हैं कि इन बैठकों में मौसम के हाल या बॉलीवुड पर तो चर्चा नही ही हुई थी। राजसत्ता का उपभोग कर रहे इस गिरोह की चिन्ता एवं चिन्तन का आज केवल एक ही विषय हो सकता है येन-केन प्रकारेन सत्ता में बने रहना। गत ढाई वर्षों के अपने इस शासन काल में इस गिरोह ने देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी साम्प्रदायिक वैमनस्य के सिवाय कुछ दिया है तो, लव जिहाद, रामजादे बनाम हरामजादे, भारत माता की जय, गौमाता की जय, राष्ट्रवाद के भड़काऊ नारे, बीफ़-बिरयानी विवाद, तिरंगा यात्रायें महंगी दालें, महंगा पेट्रोल, महंगे रेल भाड़े, महंगी बिजली आदि-आदि।

जनता को धोखा देने के लिये चुनावी जुमले, शिलान्यासों का पाखंड व गौ रक्षकों के गिरोहों द्वारा दलितों को मारना पीटना और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का प्रलाप कि दलितों की बजाय उन्हें गोली मार दो

भाजपा-संघ की इस वक्त सबसे बड़ी चिन्ता यू. पी. और पंजाब के चुनाव हैं; चिन्ता तो गुजरात व गोआ की भी कम नहीं है, परन्तु तुरन्त सिर पर पड़ने वाला वह यू पी चुनाव है जहां ढाई बरस पहले भाजपा ने 80 में से 75 लोकसभा सीटें जीती थीं और आज विधान सभा की 420 में से भी 75 जीतनी भारी पड़ रही हैं। पंजाब जहां गत 10 वर्षों से भाजपा अकालियों के साथ मिलकर शासन कर रही है। इस दौरान पंजाब की जो तबाही की गयी है, जिस तरह से पूरी पंजाबी नस्ल को नसेड़ी बना दिया गया है, जिस तरह से सरकारी लूट-खसूट का दौर चला है, उसे देखते हुए इस सरकारी गठबंधन की सांसें फूली हुई हैं।

आदि। अपनी ढाई साल की उपलब्धियां गिनवाने पर अरबों रुपया खर्च करके सरकार बताती है कि उसने स्वच्छता अभियान चलाया। कैसा है यह अभियान, इसे विज्ञापनों के सचित्र घेरे से निकल कर हर देशवासी अपने शहर के हर गली मोहल्ले में साक्षात देख रहा है। इससे बड़ा कोई पाखंड हो नहीं सकता। फ़सल बीमा योजना भी कोई कम बड़ा फ्रॉड नहीं है। न चाहते हुए भी किसानों से जबरन फ़सल बीमा की किश्तें वसूल की जा रही हैं। वास्तव में बीमा अपने आप में ही एक बड़ा कुचक्र होता है। कोई भी बिमा कम्पनी घाटे में चलाने के लिये नहीं बनाई जाती। यदि घाटा होने लगा तो कम्पनी फ़ेल हो जायेगी और मुनाफ़ा तभी हो सकता है जब बीमा कराने वाला घाटा खाये। जाहिर है इसमें घाटा खाने वाला तो किसान ही रहेगा। इसी तरह की अटल व अन्य पैंशन योजनायें हैं जिनसे केवल पूंजीपति कम्पनियों को ही लाभ हो रहा है न कि आम जनता को।

भाजपा-संघ की इस वक्त सबसे बड़ी चिन्ता यू. पी. और पंजाब के चुनाव हैं; चिन्ता तो गुजरात व गोआ की भी कम नहीं है, परन्तु तुरन्त सिर पर पड़ने वाला वह यू पी चुनाव है जहां ढाई बरस पहले भाजपा ने 80 में से 75 लोकसभा सीटें जीती थीं और आज विधान सभा की 420 में से भी 75 जीतनी भारी पड़ रही हैं। पंजाब जहां गत 10 वर्षों से भाजपा अकालियों के साथ मिलकर शासन कर रही है। इस दौरान पंजाब की जो तबाही की गयी है, जिस तरह से पूरी पंजाबी नस्ल को नसेड़ी बना दिया गया है, जिस तरह से सरकारी लूट-खसूट का दौर चला है, उसे देखते हुए इस सरकारी गठबंधन की सांसें फूली हुई हैं।

हरियाणा के चुनाव बेशक अभी दूर हैं, परन्तु कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनायेगी, देर सबेर सामना तो यहां भी चुनावों का करना ही है। और जिस तरह से सरकार का काम-काज चल रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि भाजपा पुनः अपने पुराने स्तर यानी 10-12 सीटों पर सिमट जायेगी।

संघ-भाजपा पानी को चाहे कितना ही बिलोते रहें, इसमें से मक्खन तो निकलने वाला है नहीं।

राजमार्ग का 6 लेन प्रोजेक्टः पूरी गुंडागर्दी पर उतरी है रिलायंस कम्पनी

फ़रीदाबाद (म.मो.) राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6 लेन प्रोजेक्ट के नाम पर अनिल अम्बानी की रिलायंस इन्फ्राचट्रक्चर ने गत 5 बरसों से पूरे शहर को बंधक बना रखा है। कभी उपायुक्त मीटिंग लेकर उन्हें समझाते हैं तो कभी स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गुजर इन्हें मीठी धमकी देते हैं तो कभी छुटभैये कांग्रेसी सड़क पर आकर प्रदर्शन करते हैं। परन्तु केन्द्र सरकार को अपनी जेब में रख कर चलने वाले अम्बानी परिवार पर इन सब बातों का कतई कोई असर नहीं।

बाटा मोड़ वाला फ़्लाईओवर 27 अगस्त से बनकर पूरी तरह से तैयार है। उस दिन के बाद से उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद पुल को आवागमन के लिये न खोल कर जनता को बिना बजह परेशान किया जा रहा है। दूसरी ओर अजरोंदा व ओल्ड चौक वाले फ़्लाईओवरों पर पिछले करीब 2-3 माह से काम बिल्कुल बन्द पड़ा है। इन पुलों पर मिट्टी अथवा राख भराई का काम बिल्कुल बन्द है। काम को इस तरह से रोक कर मानो अनिल अम्बानी कह रहा हो कि 'नहीं' करता काम कर लो मेरा क्या करोगे?

सत्ता के गलियारों में पहुंच रखने वालों की यही तो ठनक होती है। ये लोग काम भी नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते और जनता से लूट वसूली भी जारी रखते हैं। उसे काम करने की जरूरत भी क्या है, क्यों करे वह काम? जो टोल टैक्स उसे काम पूरा करने के बाद मिलना चाहिये था उसे तो वह गत 6 बरसों से वसूल रहा है। फ़िर काम करने की जरूरत रह कहां गयी? इनके चन्दों पर चलने वाली सरकार में इतना दम नहीं कि इसकी टोल वसूली बन्द कर दे और करीब डेढ वर्ष पूर्व 'कैग' की रिपोर्ट के आधार पर अनिल अम्बानी को हवालात में डाल दें। जी हां, कैग ने इतनी विस्तृत रिपोर्ट में कहा था कि टोल वसूली का मात्र एक चौथाई भाग ही सड़क निर्माण पर खर्च हो रहा है। एक चौथाई भाग फ़र्जी तौर पर निर्माण कार्य में दिखाया गया है। मौके पर कैग को वहां न तो कोई लेबर मिली, न सामान और मशीनरी। शेष दो चौथाई वसूली को अनिल अपनी विभिन्न कम्पनियों में लगा रहा है। इस धोखाधड़ी के लिये अनिल को सीधे गिरफ़्तार किया जा सकता था, लेकिन जब मोदी सरकार खुद ही उसके एहसानों तले दबी हो तो गिरफ़्तार कौन करे?

अनिल से प्रेरित होकर सुभाष चन्द्रा और गले आन पड़ा

हरियाणा की जनता को लूटने के लिये शायद एक अनिल अम्बानी काफ़ी नहीं था। इसलिये भाजपा सरकार ने केएमपी (कुंडली मानेसर पलवल) का लूट प्रोजेक्ट ज़ी टीवी के मालिक एवं भाजपा द्वारा नये-नये पैसे से बनाये गये राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चन्द्रा को सौंप दिया है। वैसे तो यह प्रोजेक्ट गुपचुप तरीके से सुभाष को पहले ही सौंपा जा चुका था। दिनांक 9 सितम्बर को हुई हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग के दौरान इस मुद्दे को लेकर मन्त्रियों के आपसी मतभेद खुल कर सामने आ गये। वित्त मंत्री अभिमन्यु और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सुभाष चन्द्र के काम की अत्यन्त धीमी गति से काफ़ी रुष्ठ थे, लेकिन संघ के इशारे पर मुख्यमंत्री खट्टर ने उन्हें थोड़ा जुर्माना लगा कर काम चालू रखने की स्वीकृति दे दी। इस पर अभिमन्यु मीटिंग बीच में ही छोड़कर निकल लिये।

दरअसल ये चन्द ऐसे उदाहरण हैं जो सिद्ध करते हैं कि विकास के नाम पर कैसे सरकारें एवं इनके लग्गुए-भग्गुए जनता को लूटने को स्वतंत्र हैं।